

क्रमांक विभाग		पृष्ठ संख्या
I	भूमिका	1
II	शिक्षा निदेशालय	4
III	उच्च शिक्षा निदेशालय	6
IV	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	8
V	स्वास्थ्य विभाग	10
VI	समाज कल्याण विभाग	12
VII	महिला एवम बाल विकास विभाग	13
VIII	अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	15
IX	परिवहन विभाग	17
X	लोक निर्माण विभाग	19
XI	भाहरी विकास विभाग	20
XII	दिल्ली भाहरी आश्रय सुधार बोर्ड	21
XIII	दिल्ली जल बोर्ड	23
XIV	उर्जा विभाग	26
XV	पर्यावरण विभाग	27
XVI	वन विभाग	29
XVII	Learnings from Outcome	30
XVIII	Way forward	33

I. आउटकम बजट 2017-18

अध्यक्ष जी,

1. यह मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली सरकार के आउटकम बजट 2017-18 के अंतर्गत दिसम्बर 2017 तक की प्रगति और उपलब्धियां इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2. पिछले वर्ष मार्च में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय मैंने दिल्ली सरकार के प्रथम आउटकम बजट की भी घोषणा की थी। आउटकम बजट तैयार करने का लक्ष्य सरकारी खर्च में उच्च स्तरीय जवाबदेही और पारदर्शिता लाना था। नागरिक और यहां तक कि चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पर विचार करते थे कि सरकार जो इतने विशाल बजट को खर्च करती है आखिर उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, और अधिकतर मामलों में उन्हें कुछ प्राथमिक कार्यक्रमों के बारे में सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध सीमित आंकड़ों या जानकारी से संतुष्ट रहना पड़ता था या फिर आरटीआई के ज़रिए जानकारी प्राप्त की जाती थी। सरकारी तंत्र में भी, कई बार कार्यक्रमों के परिणामों और हासिल की गयी उपलब्धियों की बजाए यह सुनिश्चित करने तक ध्यान सीमित रहता है कि चुने हुए कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और आवंटित धन खर्च किया गया है। हमने पिछले वर्ष इसे बदलने का फैसला किया।
3. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का यह विश्वास है कि सरकार और नागरिकों के बीच संबंध किसी पवित्र अनुबंध से कम नहीं है। यह अनुबंध कर दाताओं द्वारा अदा किए गये धन के बदले में समाज को यथासम्भव सर्वोत्कृष्ट परिणाम और लाभ प्रदान करने से संबंधित है। परंतु यह सूचित करना भी

महत्वपूर्ण है कि निर्धारित खर्च के लिए कौन से परिणाम हासिल करने की योजना बनाई गयी थी और अंततः क्या हासिल किया गया । अतः हमने पिछले वर्ष मार्च 2017 में एक व्यापक आउटकम बजट तैयार किया, जिसमें दिल्ली सरकार के 34 विभागों और एजेन्सियों के साथ 1900 आउट पुट व आउटकम संकेतकों और मेज़रेबल इण्डिकेटर्स शामिल किए गये। भारत में, दिल्ली सरकार आउटकम बजट की ऐसी वृहद समीक्षा करने वाली अपनी तरह की पहली सरकार बन गयी है।

4. आज हम एक और बेंचमार्क कायम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि यदि आउटकम बजट का प्रयोजन सरकारी खर्च में जवाबदेही तय करना है तो हम अगले वर्ष का बजट प्रस्तुत करने से पहले आउटकम बजट 2017–18 के संदर्भ में दिसम्बर 2017 तक हासिल की गयी उपलब्धियों का व्यापक ब्योरा सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को अवश्य उपलब्ध कराएंगे।

5. अध्यक्ष जी, उपलब्धियों की स्थिति को उजागर करने से पहले मैं कुछ उदाहरण देकर यह बताना चाहूंगा कि आउटकम बजट में कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए और यह बजट रेगुलर बजट से किस तरह अलग है।

(क) नियमित बजट हमें यह बताता है कि मोहल्ला क्लिनिकों के निर्माण के लिए धन आवंटित किया गया है, परंतु इस बात की जानकारी हमें केवल आउटकम बजट से ही मिल सकती है कि कितने क्लिनिक बनाने की योजना थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि दैनिक आधार पर इन क्लिनिकों से कितने लोगों को लाभ पहुँचा।

(ख) इसी प्रकार, रेगुलर बजट हमें यह बताता है कि सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से संबद्ध बच्चों का प्राइवेट

स्कूलों में निःशुल्क दाखिला सुनिश्चित किया जाए। परंतु इस बात की जानकारी केवल आउटकम बजट से मिलेगी कि पिछले वर्ष आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए कितनी सीटें उपलब्ध थी, इन सीटों के लिए कितनी संख्या में बच्चों ने आवेदन किया और अंततः कितने बच्चों ने दाखिला लिया।

6. इस तरह आउटकम बजट दिल्ली सरकार की प्रत्येक प्रमुख योजना और कार्यक्रम के निष्पादन के बारे में दो प्रकार के **indicators** प्रदान करता है: **Output indicators** और **Outcome indicators**। **Output indicators** हमें बताते हैं कि सरकारी विभागों को किस तरह की सेवाएँ या ढाँचा प्रदान करना है (जैसे बनाए जाने वाले मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या), जबकि **Outcome indicators** हमें इस बात की सही जानकारी देते हैं कि इन कार्यक्रमों से कितने लोगों को लाभ पहुँचा (मोहल्ला क्लिनिकों में कितनी संख्या में रोगी पहुँचे)।
7. अध्यक्ष जी एक वर्ष पहले जब मैंने इस सदन में अपनी सरकार का पहला आउटकम बजट प्रस्तुत किया था, तो मैंने कहा था कि यह माध्यम, विभागों की तिमाही प्रगति का भी आधार बनेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वैसे ही हुआ जैसी हमने योजना बनाई थी। इस वर्ष समीक्षा के दो दौर हुए—पहला जुलाई/अगस्त 2017 में और दूसरा दिसम्बर 2017 में। इनकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री ने अथवा मैंने स्वयं की। यह समीक्षा की गयी कि आउटकम बजट में वर्णित वार्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में सभी विभागों ने तिमाही के दौरान कितनी प्रगति की। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभूतपूर्व कार्य यह हुआ कि हमारी सरकार ने आउटकम बजट प्रतिबद्धताओं के संदर्भ

में प्रगति संबंधि सभी आकड़े वर्ष की पहली छमाही (अर्थात सितम्बर 2017 तक) के बाद जनता के समक्ष उजागर किए।

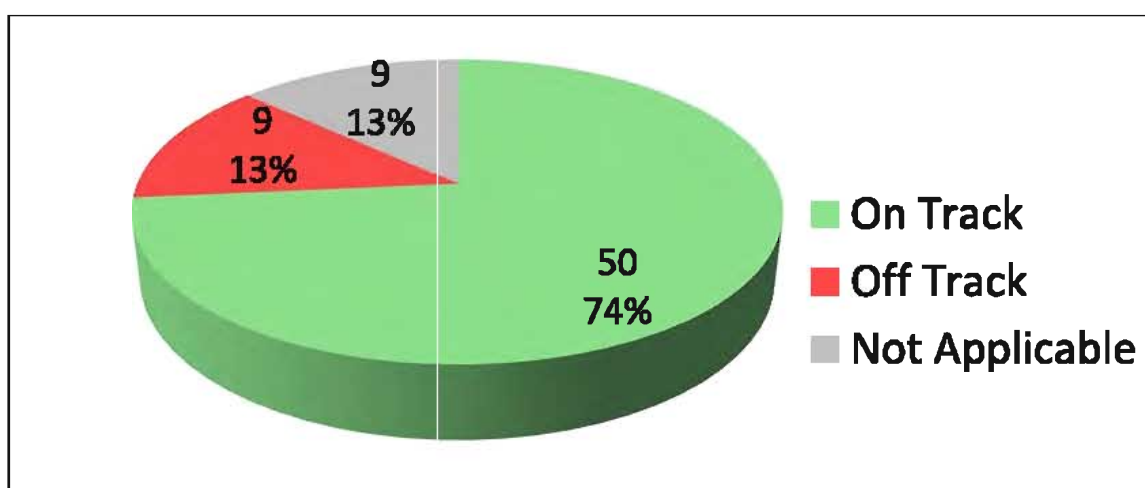
8. मैं अब वर्ष 2017–18 के आउटकम बजट के अंतर्गत **Output** और **Outcome Indicators** के अनुसार प्रमुख विभाग वार प्रगति का सारांश प्रस्तुत करूंगा। समय की कमी के कारण मैं केवल **14** महत्वपूर्ण विभागों का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष चूंकि अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः मैं वर्ष के पहले नौ महीनों अप्रैल से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में हासिल की गयी उपलब्धियों की जानकारी सदन को दूंगा, इसके अतिरिक्त **Outcome** बजट के लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक विभाग की प्रगति की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए योजना विभाग ने प्रत्येक विभाग के **indicators** का ऑन-ट्रैक (यह जानने के लिए कि क्या उन्होंने दिसम्बर 2017 तक 70 प्रतिशत प्रगति की है) या ऑफ-ट्रैक (अर्थात क्या निष्पादन 70 प्रतिशत से कम रहा है) मुल्यांकन किया है। कुछ संकेतकों को, जहां इन्हें लागू करने की तिथि वर्ष के उसके अंतिम तिमाही में आती है उन्हें “नॉट-अप्लिकेबल” चिह्नित किया गया है।
9. अध्यक्ष, जी मैं अब आउटकम बजट 2017–18 के संदर्भ में प्रमुख विभागों की स्थिति प्रस्तुत करता हूँ।

II. शिक्षा निदेशालय

- i. कुल 153 आउटपुट और आउटकम संकेतकों सहित चालू वित्त वर्ष के आउटकम बजट में शिक्षा निदेशालय की 27 योजनाएं और कार्यक्रम शामिल किये गये। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण निम्न प्रकार है :—

संकेतको की कुल संख्या:	153
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	68
आन-ट्रैक संकेतको की संख्या:	50(74%)
आफ-ट्रैक संकेतको की संख्या:	9 (13%)
संकेतक लागू नहीं:	9 (13%)

ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

- 156 स्कूलों के लक्ष्य की तुलना में दिल्ली सरकार के 155 स्कूलों में पहली बार नर्सरी और केजी कक्षाएं शुरू की गई हैं। इन स्कूलों में, कुल 6200 सीटें उपलब्ध थीं, जिनमें से 80 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत सीटें भरी गयी हैं।
- पहली बार, कक्षा पुस्तकालयों की स्थापना 6300 कक्षाओं के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले स्कूलों के प्राथमिक वर्गों के 4178 कक्षाओं में की गई है।
- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के कुल 24,500 छात्रों को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया

के माध्यम से गैर-अनुदानित निजी स्कूलों में भर्ती कराया गया है। पिछले साल ऐसे भर्ती हुए छात्रों की संख्या 20,000 थी।

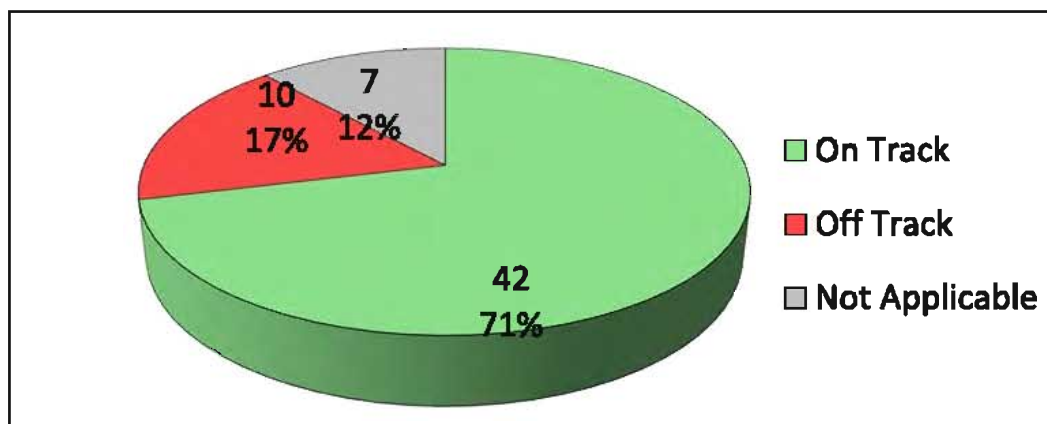
- प्रसन्नता गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष पहल के रूप में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पहली बार, सभी सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया गया।
- व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए, वार्षिक लक्ष्य 250 के मुकाबले इस वर्ष 359 व्यावसायिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
- हमारी सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है। पिछले वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 47,000 शिक्षकों की तुलना में, 1,00,300 शिक्षकों को एससीईआरटी और डीआईईटी द्वारा दिसंबर 2017 तक प्रशिक्षित किया गया। इसमें से कुछ शिक्षकों को एक बार से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना शामिल है।

III. उच्च शिक्षा निदेशालय

- कुल मिलाकर 193 आउटपुट और आउटकम संकेतकों के साथ 20 योजनाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों को चालू वर्ष के आउटकम बजट में शामिल किया गया है। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण निम्न प्रकार है –

संकेतकों की कुल संख्या:	193
महत्वपूर्ण संकेतकों की कुल संख्या:	59
आन-ट्रैक संकेतकों की संख्या:	42(71%)
आफ-ट्रैक संकेतकों की संख्या:	10(17%)
संकेतक लागू नहीं:	7 (12%)

ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:-

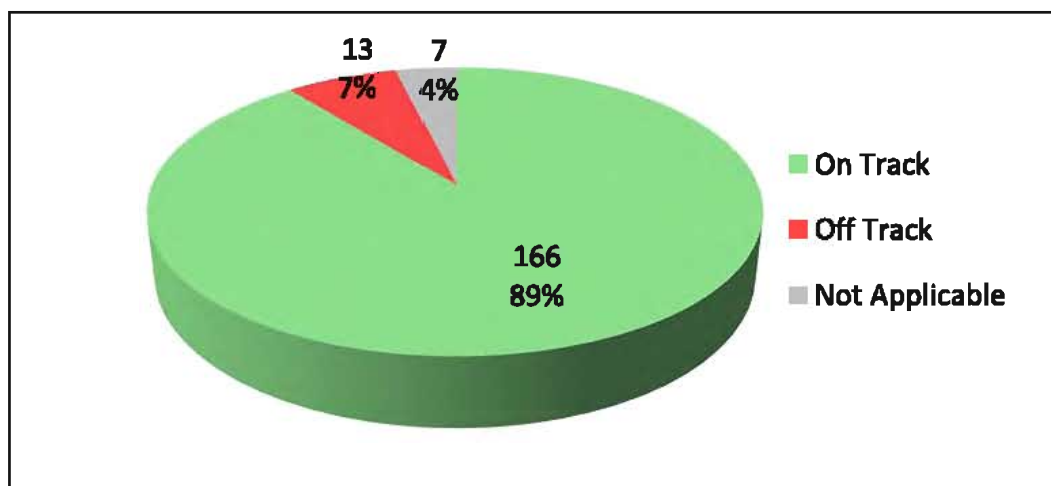
- 2016-17 में भर्ती 7392 छात्रों के मुकाबले सभी 12 शत-प्रतिशत सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों, एनएलयू, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एवं दिरम (DIHRM) में कुल 8603 छात्रों ने इस वर्ष प्रवेश लिया।
- पिछले साल प्रकाशित 524 शोध पत्रों की तुलना में 2017-18 में सभी महाविद्यालयों के अंतर्गत दिसंबर 2017 तक प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या 411 है।
- “दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना” के तहत 410 आवेदनों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर 17 के अंत तक 150 आवेदन प्राप्त हुए। इस वर्ष सरकार ने “मैरिट कम मिन्स सहायता योजना” भी शुरू की है जिसके लिए “दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट” के कोष का इस्तेमाल किया जाएगा।
- शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज का निर्माण जुलाई 2017 में पूरा हुआ जो कि इस वर्ष के आउटकम बजट के तहत लक्षित किया गया था, 2017-18 शैक्षणिक सत्र के दौरान महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 964 है जो 3 वर्षों में 2000 तक पहुंचने की उम्मीद है।

IV. निदेशालय प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा

- i. कुल मिलाकर 288 आउटपुट और आउटकम संकेतक के साथ 24 योजनाएं और तकनीकी शिक्षा संस्थानों को चालू वर्ष के आउटकम बजट में शामिल किया गया है। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतक का विवरण निम्न प्रकार है

संकेतको की कुल संख्या:	288
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	186
आन—ट्रैक संकेतको की संख्या:	166(89%)
आफ—ट्रैक संकेतको की संख्या:	13 (7%)
संकेतक लागू नहीं:	7 (4%)

- ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



- iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

- 2016–17 में 6445 छात्रों के मुकाबले 2017–18 में तकनीकी कालेज और विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 7083 छात्रों ने प्रवेश लिया।

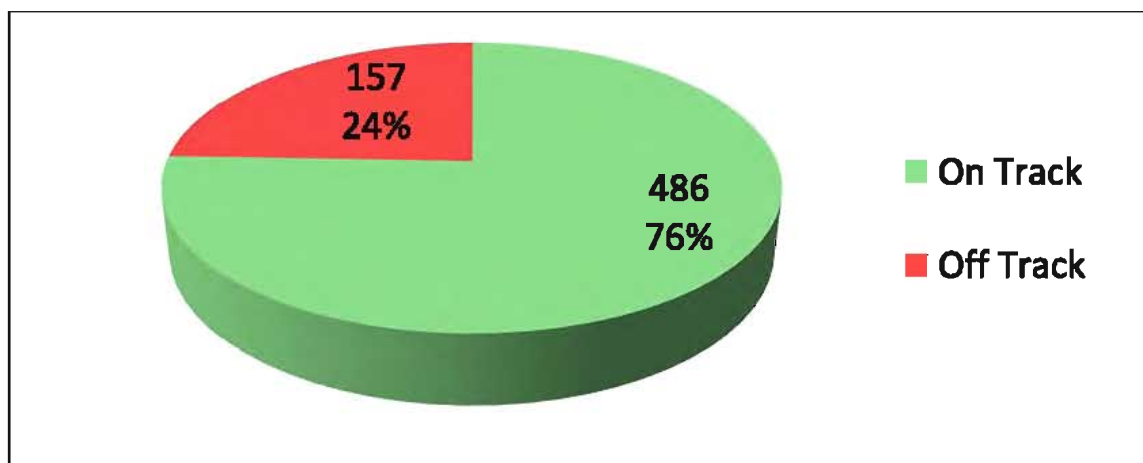
- 2016–17 में 2597 छात्रों के मुकाबले 2017–18 में विभिन्न तकनीकी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में पढ़ते हुए 2332 छात्रों (दिसंबर '17 तक) के लिए कैपस प्लेसमेंट की पेशकश की गई ।
- प्रायोजित/ औद्योगिक परामर्श से कॉलेजों / विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पन्न राजस्व 2017–18 में करीब 15.03 करोड़ रुपये है। 2016–17 में यह आंकड़ा 12.39 करोड़ रुपये था।
- 407 संकायों ने 2017–18 दिसंबर 2017 तक 994 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। 2016–17 के दौरान, 347 संकायों ने 1273 रिसर्च पेपर पत्र प्रकाशित किए।
- विश्व स्तरीय कौशल केंद्र के संबंध में, 2017–18 के दौरान 764 छात्रों ने 2016–17 में 663 के मुकाबले उत्तीर्ण किया। 80 प्रतिशत उत्तीर्ण छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने के 3 महीने के भीतर पूर्णकालिक रोजगार मिला जबकि बाकी छात्र उच्च अध्ययन और उद्वेगशीलता की ओर चले गये।
- 2017–18 के दौरान पॉलिटेक्निक में 4068 छात्रों ने प्रवेश लिया जबकि 2016–17 में 3580 छात्रों ने प्रवेश लिया था। 2016–17 में 2500 छात्रों की तुलना में 2017–18 में 3087 छात्र उत्तीर्ण हुए।
- दिल्ली सरकार द्वारा अपने विभिन्न उच्च एवं तकनीकी संस्थानों में स्थापित 11 इनक्यूबेशन सेंटर के लिए अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। वर्तमान छात्रों/पूर्व छात्रों और अध्यापकों के द्वारा 76 स्टार्ट-अप्स शुरू किए गये हैं जबकि वार्षिक लक्ष्य 60 तय किया गया था।

V. स्वास्थ्य

- i. 56 योजनाओं में 764 आउटपुट और 921 आउटकम संकेतको को आउटकम बजट में सम्मिलित किया गया है। इनमें से 643 संकेतक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में योजना विभाग द्वारा त्वरित समीक्षा के लिए चुने गये हैं।

संकेतको की कुल संख्या:	1685
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	643
आन— ट्रैक संकेतको की संख्या:	486(76%)
आफ—ट्रैक संकेतको की संख्या:	157 (24%)

- ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



- iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

- 1000 क्लिनिकों के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर 2017 तक 160 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गये हैं जिनमें कुल 32 लाख रोगियों ने स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त की हैं।

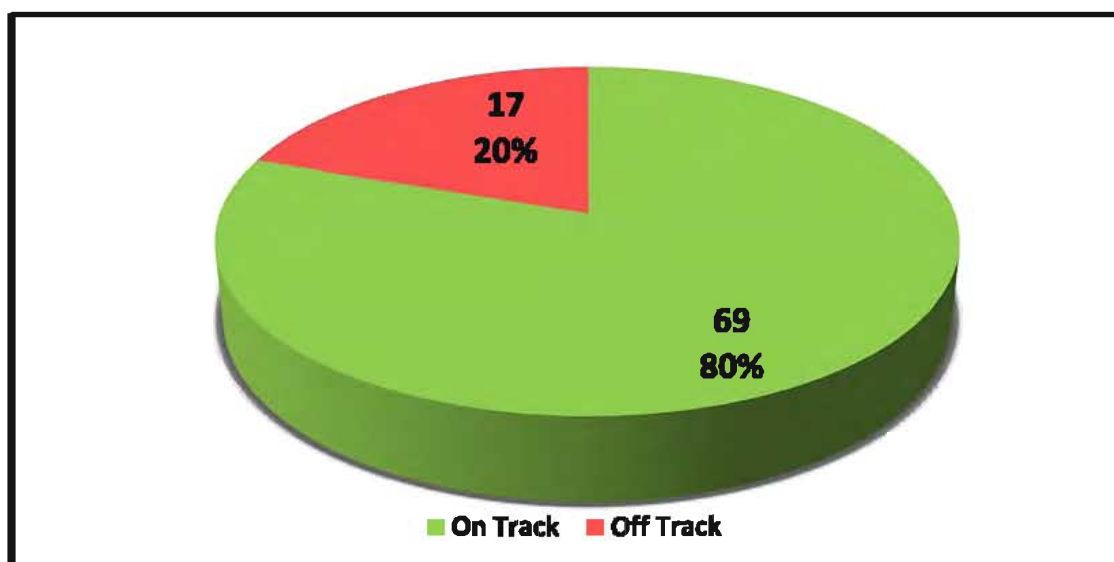
- स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 300 स्कूलों के लक्ष्य की तुलना में 298 स्कूलों में 2.76 लाख छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जाँच की गयी। इन जाँचे गये छात्र-छात्राओं में से 1.01 लाख छात्र-छात्राओं को सामान्य स्वास्थ्य संबंधी मामलों में परामर्श/चिकित्सा सुविधा दी गयी।
- 1218 स्कूलों के लगभग 9 लाख छात्र-छात्राओं को साप्ताहिक आयरन फॉलिकएसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम के तहत कवर किया गया था और 1613 स्कूलों के लगभग 12 लाख छात्र-छात्राओं की कीड़ों से मुक्ति के व्यापक कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।
- 2.52 लाख बच्चों (9-11 माह के आयु वर्ग) के लक्ष्य की तुलना में, लगभग 1.90 लाख बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया।
- 1.40 लाख इंस्टिट्यूशनल डिलीवरी प्रसव के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से 1 लाख इंस्टिट्यूशनल डिलीवरी कराई गयीं।
- वर्ष 2016-17 तक टीबी से पीड़ित कुल 57000 रोगियों की तुलना में माह दिसम्बर 2017 तक कुल 48879 टीबी से पीड़ित रोगियों का उपचार किया गया।
- औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा प्रतिमाह लगभग 277 दवाई बिक्री फर्मों का निरीक्षण किया गया और नियमों का उलंघन करने वाली औसतन 50 फर्मों के प्रतिमाह लाइसेंस रद्द किए गये।
- दिल्ली के 32 सरकारी अस्पतालों में लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त की।

VI. समाज कल्याण विभाग

- i. आउटकम बजट 2017-18 में 26 कार्यक्रमों /योजनाओं को शामिल किया गया है , जिसमें कुल 227 आउटपुट आउटकम संकेतक है तथा इसमें से 86 क्रिटिकल संकेतक हैं ।

संकेतको की कुल संख्या:	227
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	86
आन- ट्रैक संकेतको की संख्या:	69 (80%)
आफ-ट्रैक संकेतको की संख्या:	17 (20%)

- ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



- iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:-

- इस वर्ष 4.20 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता दी गयी है जबकि वर्ष 2016-17 में लगभग 3.83 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता दी गयी थी ।
- वर्ष 2016-17 में लगभग 70,000 दिव्यांगों को आर्थिक सहायता की तुलना में इस वर्ष 2017-18 में 75603 दिव्यांगों को आर्थिक सहायता दी गयी है ।

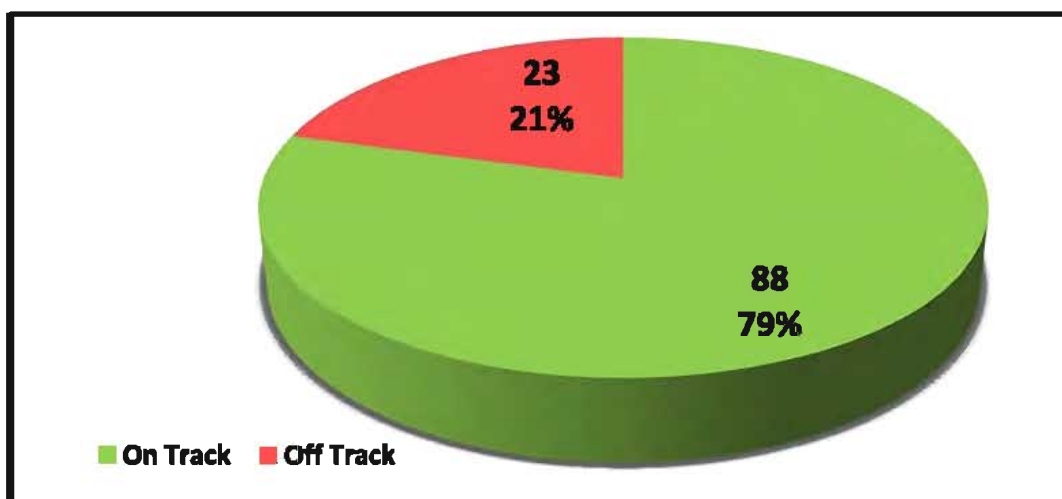
- वर्ष 2016–17 में 7000 परिवारों को एक मुश्त आर्थिक सहायता की अपेक्षा इस वर्ष 2781 परिवारों को एक मुश्त आर्थिक सहायता दी गयी है ।
- 5 हाफ वे होम्स/लॉन्ग स्टे होम्स का निर्माण पूरा हो चुका है और इनमें से 3 होम्स का संचालन भी शुरू हो चुका है ।
- विभाग मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 6 होम्स का संचालन कर रहा है इन होम्स की कुल क्षमता 810 सदस्य हैं तथा इनमें 1169 सदस्य रह रहे हैं ।
- विभाग वर्ष 2017–18 में, 10 ओल्डऐज होम्स का निर्माण कार्य शुरू करने के लक्ष्य की अपेक्षा में मात्र 2 ओल्डऐज होम्स का निर्माण शुरू कर सका है ।

VII. महिला एवं बाल विकास विभाग—

- आउटकम बजट 2017–18 में 16 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें कुल 164 आउटपुट/आउटकम संकेतक है तथा इसमें से 111 क्रिटिकल संकेतक हैं ।

संकेतको की कुल संख्या:	164
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	111
आन— ट्रैक संकेतको की संख्या:	88 (79%)
आफ—ट्रैक संकेतको की संख्या:	23 (21%)

ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

- 2016—17 में 1.77 लाख निःसहाय महिलाओं की तुलना में इस वर्ष 2 लाख निःसहाय महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी गयी है। 24000 नये लाभार्थी जोड़े गये जबकि 1154 लाभार्थी विभिन्न कारणों से हटाये गये।
- आई सी डी एस कार्यक्रम में 10897 आंगनवाड़ी सेंट्रों के अंतर्गत लगभग 12 लाख बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण, आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा और प्री स्कूल एजुकेशन आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- 100 प्रतिशत टारगेट की तुलना में दिसम्बर 2017 तक 62 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेंट्रों पर एडल्ट वेटिंग स्केल हैं।
- 1,23,112 के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 1,13,874 किशोर बालिकाओं ने पूरक पोषण आहार की सुविधा तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी सबला एवं किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत प्राप्त की।

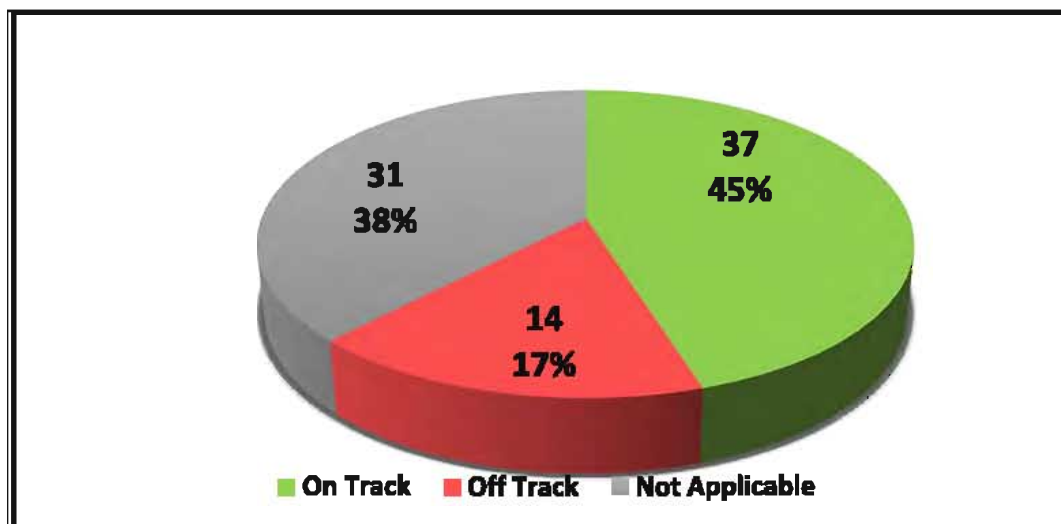
- लाडली योजना के अंतर्गत 75000 नामांकन के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर 2017 तक 68327 नामांकन के प्रार्थना पत्र विभाग को मिल चुके हैं और इनमें से 16263 का नामांकन दिसम्बर 2017 तक हो चुका है।
- 93508 नवीनीकरण की तुलना में 50696 नवीनीकरण लाडली योजना के अंतर्गत किये गए हैं।
- 60,000 वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 27216 छात्राओं को परिपक्वता राशि दी गयी है।

VIII. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

- आउटकम बजट 2017-18 में 15 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें कुल 105 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं तथा इसमें से 82 क्रिटिकल संकेतक हैं।

संकेतको की कुल संख्या:	105
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	82
आन-ट्रैक संकेतको की संख्या:	37(45%)
आफ-ट्रैक संकेतको की संख्या:	14(17%)
संकेतक लागू नहीं:	31(38%)

ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:-

- सभी स्कॉलरशिप/ आर्थिक सहायता और प्रतिपूर्ति योजनाओं के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2018 थी।
- विभाग ने पिछले वर्षों के लिए 41788 विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की।
- पिछले वर्षों के लिए 542069 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की स्टेशनरी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों (कक्षा 1-12) व पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों (कक्षा 6 से 12) के 477296 विद्यार्थियों को पिछले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी गयी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के 13177 विद्यार्थी जो कि तकनीकी /व्यवसायिक कॉलेज/ इन्सीट्यूशन/ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं छात्रवृत्ति दी गई है।

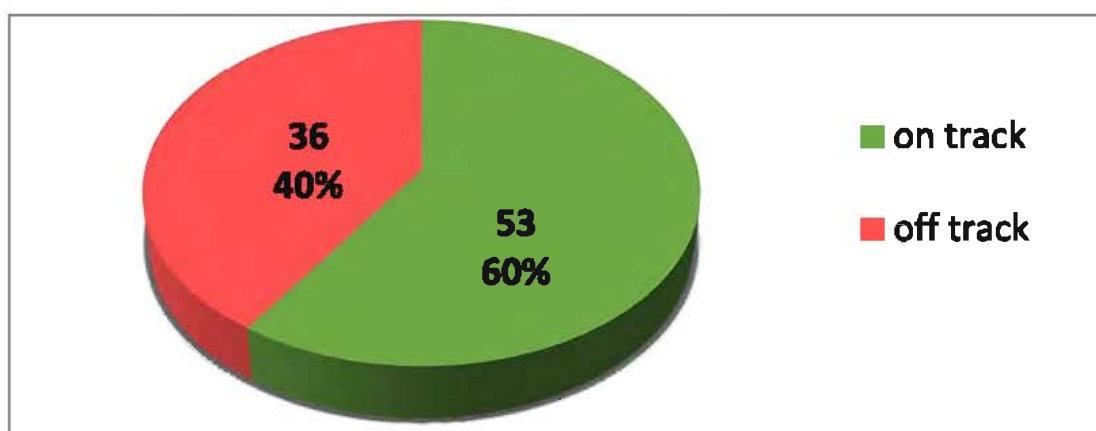
- ईसापुर गांव में 600 कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लक्ष्य की तुलना में 562 विद्यार्थी आवासीय स्कूल में पढ़ रहे हैं।
- अनुसूचित जाति बस्ती के सुधार कार्यों के 24 टेंडर के लक्ष्य की तुलना में 15 टेंडर दिये गए।
- चौपाल व सामुदायिक केंद्रों की सुधार के लिए 17 कार्यों के लक्ष्य की तुलना में 17 टेंडर दे दिये गये और 15 कार्य पूर्ण हो गये।

IX. परिवहन

- आउटकम बजट 2017–18 में 10 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें कुल 102 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं तथा इसमें से 89 क्रिटिकल संकेतक हैं।

संकेतकों की कुल संख्या:	102
महत्वपूर्ण संकेतकों की कुल संख्या:	89
आन-ट्रैक संकेतकों की संख्या:	53(60%)
आफ-ट्रैक संकेतकों की संख्या:	36(40%)

- आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

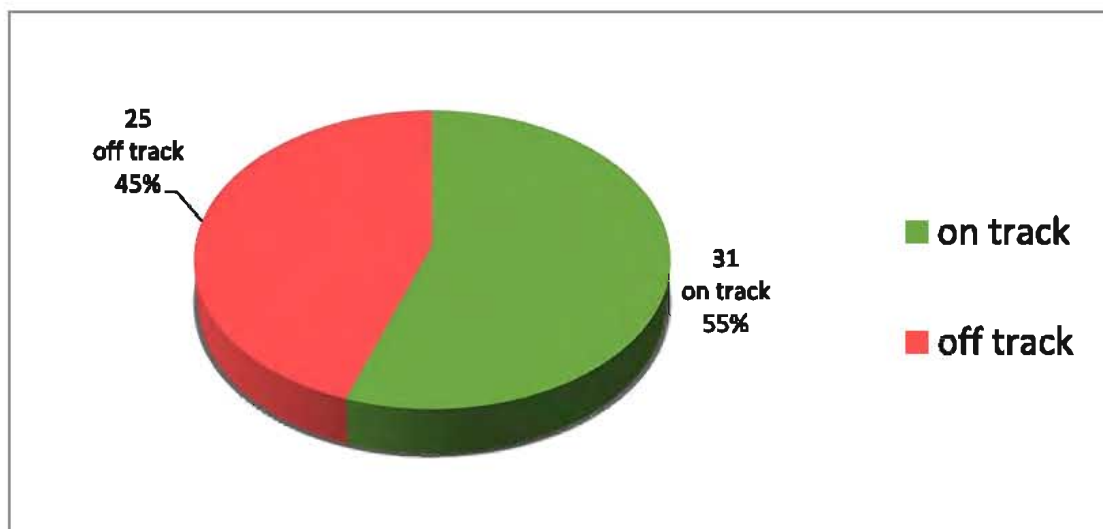
- क्लस्टर बसों तथा डीटीसी बसों योजना के अंतर्गत 40 लाख के लक्ष्य के मुकाबले औसत दैनिक यात्री संख्या 41.90 लाख प्रतिदिन तक बढ़ गयी है।
- हालांकि, इसी समय में, दिल्ली मेट्रो की औसतन दैनिक सवारी जो कि वर्ष 2016—17 में 28 लाख थी और वर्ष 2017—18 में 30 लाख पहुँचने का लक्ष्य था, वास्तव में घटकर 25.7 लाख हो गया है।
- क्लस्टर बस योजना के अंतर्गत औसत बेड़े का उपयोग 89 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 97 प्रतिशत बढ़ गया है और औसत लोड़ फैक्टर 84 प्रतिशत तक बढ़ गया है।
- वर्ष 2017—18 के लिए निर्धारित 55 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 37.27 लाख प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किए गये।
- वर्ष 2016—17 में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं रखने के कारण काटे गये 18401 चालान की तुलना में इस वर्ष दिसम्बर तक 22706 चालान काटे गये।
- वर्ष 2017—18 के लिए 2.85 लाख के लक्ष्य की तुलना में 2.11 लाख वाहनो को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए गये।
- 11 बस डिपों की तुलना में 7 नए बस डिपो बनाए गये। बस डिपों में बस पार्किंग क्षमता 6100 बसों से बढ़कर 7174 बसें हो गयी।

X. लोक निर्माण विभाग

- i. आउटकम बजट 2017-18 में 24 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें कुल 122 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं तथा इसमें से 56 क्रिटिकल संकेतक हैं।

संकेतकों की कुल संख्या:	122
महत्वपूर्ण संकेतकों की कुल संख्या:	56
आन-ट्रैक संकेतकों की संख्या:	31(55%)
आफ-ट्रैक संकेतकों की संख्या:	25(45%)

- ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



- iii. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति:—

- लोक निर्माण विभाग भिन्न-भिन्न आरओडब्ल्यू वाली 1260 किलो मीटर सड़कों का रख-रखाव कर रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 300 किलो मीटर लम्बी सड़कों सुदृढ़ करने की योजना बनाई गयी थी। लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निम्नलिखित हिस्सों को सुदृढ़ किया गया:—

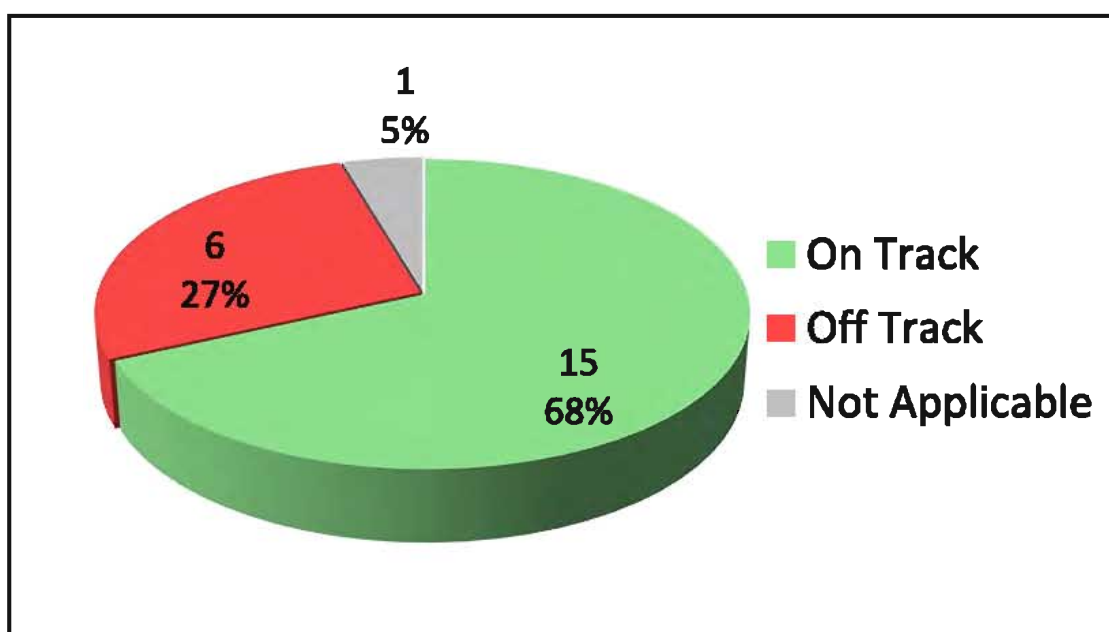
- 10 किलो मीटर के लक्ष्य की तुलना में 7 किलो मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सुदृढ़ किया गया।
- 41.47 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले रिंग रोड और आउटर रिंग रोड की 37 किलोमीटर लम्बी रोड को सुदृढ़ किया गया।
- 115 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 111 किलोमीटर लम्बी मुख्य सड़क से जोड़ने वाली अंदरूनी सड़को को सुदृढ़ किया गया।
- 135 किलो मीटर के लक्ष्य के मुकाबले 30 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाली 122 किलो मीटर सड़को को सुदृढ़ किया गया।
- बारापुला फेज-3 परियोजना का वर्ष 2017-18 के लिए 70 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 52 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
- साकेत मेट्रो स्टेशन पर एक एफओबी का कार्य पूरा हो चुका है और 4 अन्य एफओबी का कार्य पूरा होने के करीब है।

XI. बाहरी विकास विभाग

- 7 कार्यक्रम/योजनाएं आउटकम बजट 2017-18 में शामिल थी जिनमें में 83 आउटपुट/आउटकम संकेतक शामिल थे। इसमें से 22 महत्वपूर्ण संकेतक हैं। विभाग के आउटपुट और आउटकम संकेतक का विवरण निम्न प्रकार है:—

संकेतको की कुल संख्या:	83
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	22
आन-ट्रैक संकेतको की संख्या:	15(68%)
आफ-ट्रैक संकेतको की संख्या:	6(27%)
संकेतक लागू नहीं:	1(5%)

ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट

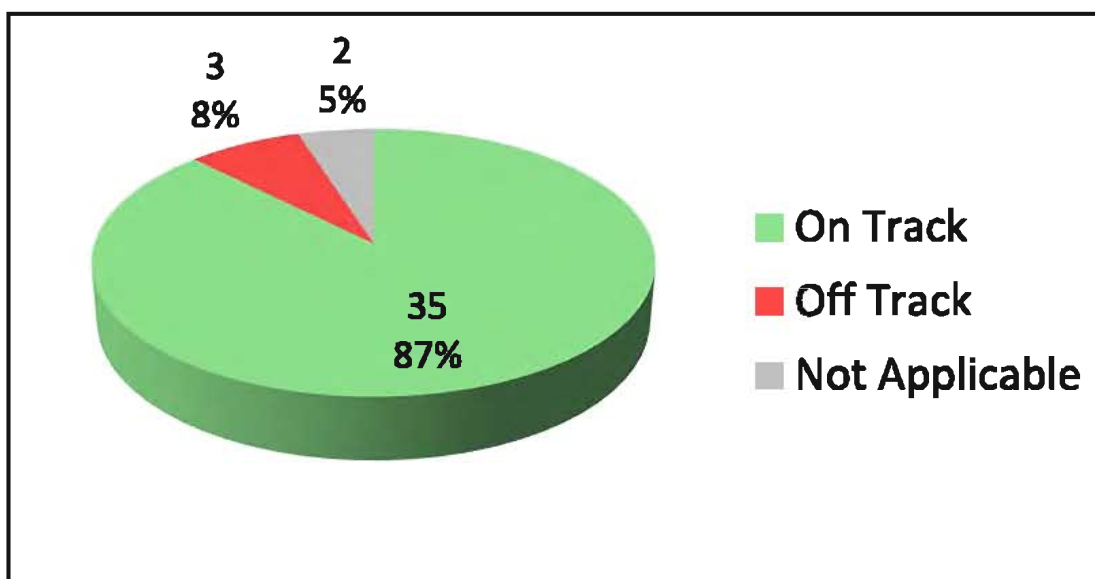


XII. दिल्ली भाहरी आश्रय सुधार बोर्ड

- आउटकम बजट 2017-18 में 9 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कुल 52 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं। आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

संकेतको की कुल संख्या:	52
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	40
आन- ट्रैक संकेतको की संख्या:	35(87%)
आफ-ट्रैक संकेतको की संख्या:	3(8%)
संकेतक लागू नहीं:	2(5%)

ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

- आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आवास, सार्वजनिक शौचालय, रात्रि निवास आदि में डीयूएसआइबी का प्रदर्शन काफी संतोषजनक है। डीयूएसआइबी द्वारा 263 यात्री निवासों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी क्षमता वर्ष 2017–18 में 20984 व्यक्ति है। वर्ष 2017–18 में रात्रि निवासों में औसतन 13178 व्यक्तियों ने निवास किया जबकि वर्ष 2016–17 में यह संख्या 11000 थी।

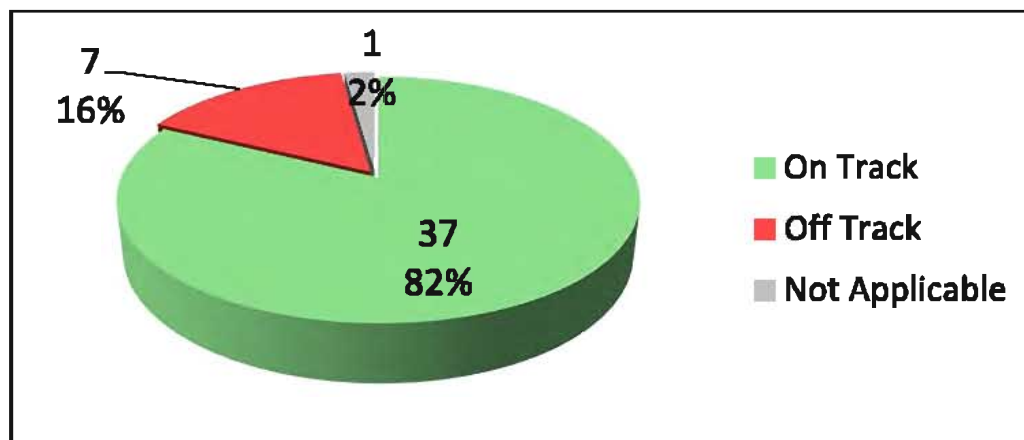
- आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आवास परियोजना का कार्यान्वयन डीयूएसआइबी द्वारा किया जा रहा है। यह सूचित किया गया है कि 15020 आवास पूर्ण होने के अग्रिम चरण में है (7620 आवास 99 प्रतिशत तथा 7400 आवास 95 प्रतिशत दिसम्बर 2017 तक पूर्ण हो चुके हैं)। 2016–17 में पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या 3064 थी।
- खुले में शौचमुक्त दिल्ली बनाने के लिए डीयूएसआइबी ने दिसम्बर 2017 तक 107 नये जन सुविधा परिसर, 3755 नई शौचालय सीट बनाई है। इसके द्वारा 112650 लोगो को लाभ मिला है, जबकि वर्ष 2016–17 में यह संख्या 55230 थी।
- अनाधिकृत कालोनियों में विविध एजेंसी द्वारा विकास कार्य लक्ष्य के अनुरूप अनुमोदित किए गये हैं।
- ट्रांस यमुना एरिया डवलपमेंट बोर्ड द्वारा 27 परियोजनाओं को अनुमोदित और इन परियोजनाओं में लगभग 50 प्रतिशत फण्ड अनुमोदित किया जा चुका है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सही प्रगति पर है और सभी 294 वार्डों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

XIII. दिल्ली जल बोर्ड

- i. आउटकम बजट 2017–18 में 20 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें कुल 127 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं तथा इसमें से 45 क्रिटिकल संकेतक हैं। आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण

संकेतको की कुल संख्या:	127
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	45
आन-ट्रैक संकेतको की संख्या:	37(82%)
आफ-ट्रैक संकेतको की संख्या:	7 (16%)
संकेतक लागू नहीं:	1 (2%)

ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

- वर्ष 2017–18 में 1209 अनाधिकृत कालोनियों को पानी की पाइप लाइन से जोड़ा गया है, जबकि वर्ष 2016–17 तक 1144 अनाधिकृत कालोनियों को पानी की पाइप लाइन से जोड़ा गया था।
- अनाधिकृत कालोनियों में जलापूर्ति के लिए दिसम्बर 2017 तक 3923 कि०मी० नई पानी की पाइप लाइन डाली गयी जबकि वर्ष 2016–17 तक 3703 कि०मी० थी।

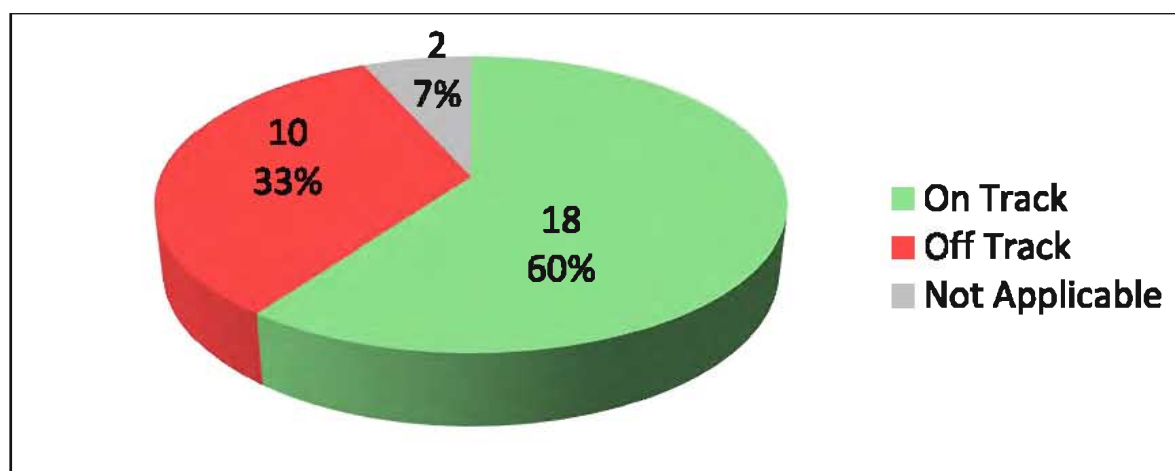
- रिसाव के कारण जल क्षति को रोकने के लिए 2064 कि०मी० की पुरानी/क्षीण पाइप लाईनों को दिसम्बर 2017 तक बदला गया है, जबकि वर्ष 2016–17 तक 1912 कि०मी० पाइप लाईनों को बदला गया था। इसके फलस्वरूप 4 एमजीडी जल बचाया गया।
- वर्ष 2017–18 के दौरान 38 और ट्यूबवेलों को जोड़ा गया तथा 51 ट्यूबवेलों को पुनर्विकसित किया गया। जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए ट्यूबवेलों और रेनीवेलो का पुनर्वास किया गया, जिसके फलस्वरूप 8 एमजीडी अधिक जल निकाला गया।
- वर्ष 2017–18 में प्रतिमाह 20 KL की मुफ्त जीवन रेखा जल देने की योजना जारी है, और लगभग 4.5 लाख उपभोक्ताओं को 31 करोड़ रुपये प्रति माह की सब्सिडी प्रदान की गयी।
- दिसम्बर 2017 तक 265 अनाधिकृत कालोनियों को सीवर प्रणाली से जोड़ा गया है, जबकि वर्ष 2016–17 तक 241 अनाधिकृत कालोनियों को सीवर प्रणाली से जोड़ा गया था।
- अनाधिकृत कालोनियों में सीवर प्रणाली के लिए दिसम्बर 2017 तक 1738 कि०मी० की नई सीवर लाईन डाली गयी जबकि वर्ष 2016–17 तक यह 1600 कि०मी० थी।
- दिल्ली में कुल 22.36 लाख चालू कनेक्शन हैं।
- वर्ष 2017–18 में पुरानी/क्षीण सीवर लाईनों को बदलने के लिए नई 873 कि०मी० की सीवर लाईन, नियमित अनाधिकृत कालोनियों में डाली गयी जबकि वर्ष 2016–17 में यह 845 कि०मी० थी।

XIV. ऊर्जा विभाग

- i. आउटकम बजट 2017-18 में 10 कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें कुल 59 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं तथा इसमें से 30 क्रिटिकल संकेतक हैं। आउटपुट और आउटकम संकेतकों का विवरण

संकेतकों की कुल संख्या:	59
महत्वपूर्ण संकेतकों की कुल संख्या:	30
आन-ट्रैक संकेतकों की संख्या:	18(60%)
आफ-ट्रैक संकेतकों की संख्या:	10 (33%)
संकेतक लागू नहीं	2 (7%)

- ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



- iii. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति:-

- दिल्ली में 2016 में 6261 मेगावाट की तुलना में वर्ष 2017 में 6526 मेगावाट की उच्चतम बिजली की मांग पूरी की गयी।
- वर्ष 2017 में बिजली व्यवस्था की नियमित समीक्षा और सख्त निगरानी के कारण दिल्ली में लोड शेडिंग केवल 0.06 प्रतिशत के स्तर पर रही

जो कि दिल्ली के इतिहास में सबसे कम स्तर की दर्ज की गयी। वर्ष 2016 में यह 0.1 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 0.14 प्रतिशत था।

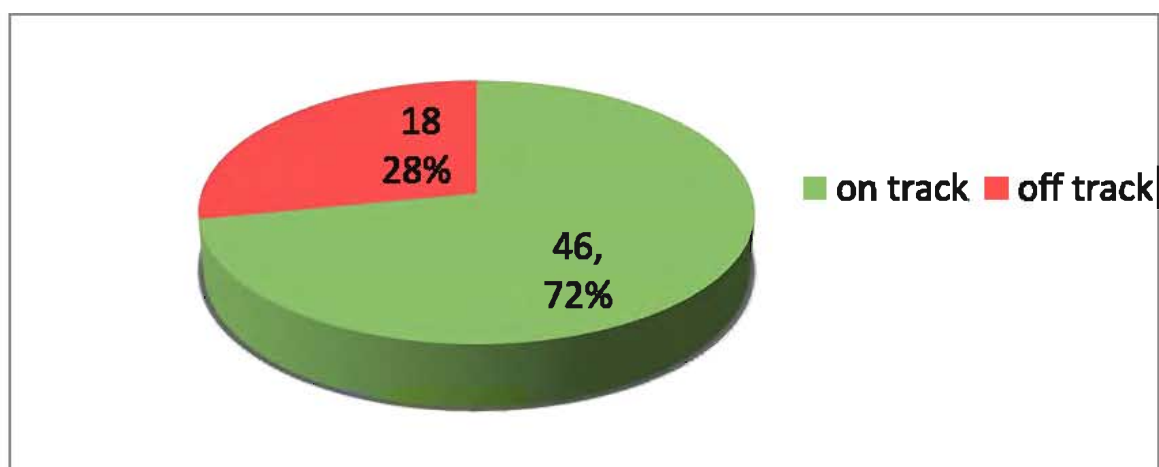
- ट्रांसमिशन कंपनी ने दिल्ली की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क में सफलतापूर्वक 220 केवी के 2 नए उप-स्टेशनों और 820 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता की वृद्धि की गयी।
- वर्ष 2016 में ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता 98.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 99.43 प्रतिशत हो गयी।
- दिल्ली में कुल सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 28 फरवरी 2018 को 81.13 मेगावाट पर पहुंच गयी। वर्ष 2016–17 में यह 49 मेगावाट थी।
- 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट तिमारपुर–ओखला (16 मेगावाट), गाजीपुर (12 मेगावाट) और नरेला–बवाना (24 मेगावाट) का दिल्ली में संचालन कुल 52 मेगावाट क्षमता के साथ हो रहा है।
- ऊर्जा विभाग ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को जो 400 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग करते हैं उन्हें 50 प्रतिशत ऊर्जा शुल्क का अनुदान दिया है। इससे 37.28 लाख उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है, जो कुल 45 लाख घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं का 82.84 प्रतिशत है।

XV. पर्यावरण विभाग

- i. **12 कार्यक्रम / योजनाओं को आउटकम बजट 2017–18 में शामिल किया गया** जिनमें कुल 79 आउटपुट/आउटकम संकेतकों में से 64 संकेतकों को महत्वपूर्ण आउटपुट/आउटकम संकेतकों की श्रेणी में रखा गया

संकेतको की कुल संख्या:	79
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	64
आन-ट्रैक संकेतको की संख्या:	46 (72%)
आफ-ट्रैक संकेतको की संख्या:	18 (28%)

ii. आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



iii. महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

- 20 नए परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को कार्यान्वित करने का लक्ष्य था जिसमें से 16 नए परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कार्यान्वित किये जा चुके हैं।
- 11546 ई-रिक्षा के मालिकों को सब्सिडी के रूप में 30.88 करोड़ रुपए अनुदान दिए गए हैं जबकि 2016-17 में 3400 लाभार्थियों के लिए 7.20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी।
- 808 लाभार्थियों को बैटरी संचालित वाहनों के लिए सब्सिडी के रूप में 1.90 करोड़ रुपए अनुदान किये गए, जबकि 2016-17 में 626 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई थी।
- "इको-क्लब" योजना के तहत 1491 स्कूल और कॉलेजों को अनुदान दिया जा चुका है जबकि लक्ष्य 1600 स्कूल और कॉलेजों का है।

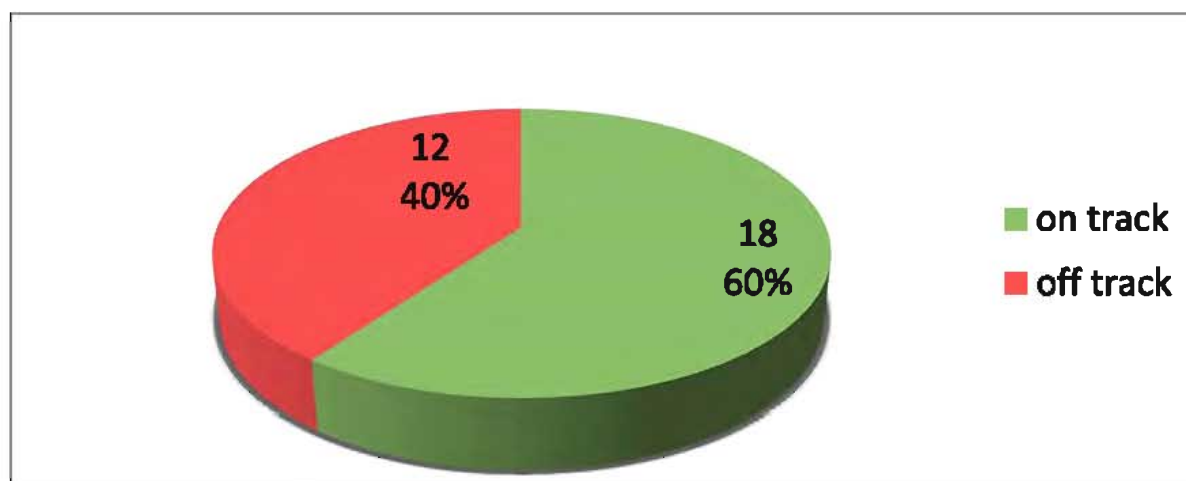
- पार्क और गार्डन सोसायटी के द्वारा 1050 आर.डब्ल्यू.ए. को पार्कों के विकास और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जबकि लक्ष्य 1350 आर.डब्ल्यू.ए. को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है।

XVI. वन विभाग

- 4 कार्यक्रम / योजनाओं को आउटकम बजट 2017-18 में शामिल किया गया जिनमें कुल 30 आउटपुट/आउटकम संकेतकों में से सभी 30 संकेतकों को महत्वपूर्ण आउटपुट/आउटकम संकेतकों की श्रेणी में रखा गया

संकेतको की कुल संख्या:	30
महत्वपूर्ण संकेतको की कुल संख्या:	30
आन- ट्रैक संकेतको की संख्या:	18 (60%)
आफ-ट्रैक संकेतको की संख्या:	12 (40%)

- आउटपुट और आउटकम संकेतकों की स्थिति पर पाईचार्ट



- महत्वपूर्ण संकेतको की स्थिति:—

- ' वन विभाग द्वारा शुरू की गई विशाल वृक्षारोपण ड्राइव के चलते दिल्ली में कुल वन और वृक्षादित क्षेत्र 2015 में 299 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2017 में 305 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

- पारिस्थितिकी टास्क फोर्स द्वारा पौधारोपण के द्वारा हरियाली क्षेत्र, 150 हेक्टेयर से बढ़कर 31 दिसम्बर, 2017 तक 200 हेक्टेयर हो गया है, जिससे वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।
- 5 लाख पौधों के पौधारोपण के लक्ष्य के मुकाबले 31 दिसंबर, 2017 तक 45 वृक्षारोपण ड्राइव के जरिये 5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं जबकि पिछले साल ऐसी 14 पौधारोपण ड्राइव ही चलाई गयी थी।
- 31 दिसंबर, 2017 तक “शहरी वनों का निर्माण और रखरखाव” योजना के तहत 12 इको झोपड़ियां तैयार की गई हैं जबकि, 2016-17 के दौरान केवल 4 इको झोपड़ियां बनाई गई थीं।
- वर्ष 2017-18 के लिए 3 तितली उद्यानों के लक्ष्य के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2017 तक दो तितली उद्यान विकसित किए गए हैं।
- वर्ष 2017-18 के लिए 5 शहरी वनों में स्थानीय लोगों की समितियां बनाने का लक्ष्य था जबकि 31 दिसंबर, 2017 तक 6 ऐसी समितियां बनाई जा चुकी हैं।

10. अभी मैंने आपके सामने उन 14 महत्वपूर्ण विभागों का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिनका दिल्ली सरकार द्वारा इस वर्ष व्यापक आउटकम बजट मूल्यांकन किया गया। आउटकम बजट मूल्यांक के अंतर्गत कवर किए गए दिल्ली सरकार के मुख्य विभागों का प्रथम 9 महीनों का ब्यौरा आज योजना विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

XVII. Learnings from Outcome Budget

11. अध्यक्ष जी, मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहूंगा, जिनसे यह पता चलता है कि आउटकम बजट प्रक्रिया ने दिल्ली सरकार और उसके

विभागों द्वारा दिल्ली के लोगों को दी जा रही सेवाओं की कार्य प्रणाली में किस तरह सुधार किया है।

12. सबसे पहली बात यह है कि आउटकम बजट से विभागों को यह बात फिर से परिभाषित करने में मदद मिली है कि वे अपने दायित्वों की सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्यावरण विभाग से एक उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए बनाए गए प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के प्रवर्तन का दायित्व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति—डीपीसीसी का है। यदि डीपीसीसी द्वारा किसी निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान को प्रदूषित करने के लिए दोषी पाया जाता है तो डीपीसीसी द्वारा सख्त दिशा—निर्देश जारी किए जाते हैं। पर्यावरण विभाग के आउटकम बजट की पहली तिमाही की समीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में यह बात आई कि वर्ष के पहले तीन महीनों में डीपीसीसी ने प्रदूषण फैलाने वाले कुल 56 उद्योगों के लिए बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए। जब यह पूछा गया कि इन प्रतिष्ठानों में से अतः कितने बंद किए गए, तो हमें पता चला कि डीपीसीसी ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखती है और यह जिला मजिस्ट्रेटों के जरिए राजस्व विभाग का दायित्व है, जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे इन प्रतिष्ठानों का बंद होना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह डीपीसीसी का काम व्यावहारिक रूप में इकाइयों को बंद करने संबंधी दिशा—निर्देश जारी करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। हमने यह निर्णय किया कि डीपीसीसी अंतिम परिणाम के लिए भी आवश्यक रूप से जिम्मेदार बनाई जानी चाहिए अर्थात् उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग अंततः बंद कर दिए गए और ऐसा करते समय वह राजस्व विभाग के साथ समन्वय कायम करे।

13. दूसरी बात यह है कि आउटकम बजट की समीक्षा से हम ऐसे कार्यक्रमों की पहचान करने में सक्षम होते हैं, जो वांछित परिणाम न दे रहे हों, तो उन्हें नया रूप देने की आवश्यकता उजागर होती है। उदाहरण के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के आउटकम बजट की समीक्षा के दौरान स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करते समय हमें पता चला कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच कुपोषण की दर बहुत ऊंची करीब 35 प्रतिशत है। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान हमने यह पाया कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत तैनात किया गया स्टाफ केवल 3 वर्ष में एक बार एक स्कूल के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच कर पाने में सक्षम है। इसके बाद हमने यह निर्णय किया कि एक बेहतर कार्यनीति अपनाई जाए, जिसमें स्कूल स्तर के करीब 350 ऐसे प्रतिबद्ध क्लिनिक होने चाहिए, जो न केवल दिल्ली में सभी स्कूली विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर नियमित और भरोसेमंद चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए।

14. आउटकम बजट सुधार से एक और प्रमुख परिवर्तन यह हुआ कि सेवाओं के वितरण के बारे में भरोसेमंद परिणामी आंकड़े जुटाने की आवश्यकता उजागर हुई। उदाहरण के लिए दिल्ली में पाइपलाइन नेटवर्क में पानी की बरबादी और रिसाव बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन उनके पास यह जानकारी कालोनी के स्तर पर, वार्ड-वार या जिला-वार उपलब्ध नहीं है और इस तरह कोई स्थानीय कार्रवाई संभव नहीं हो पाती है। दिल्ली जल बोर्ड के मूल्यांकन से दिल्ली जल बोर्ड के समूचे पाइपलाइन नेटवर्क में **District Meter Areas**, वाटर-फ्लो मीटर लगाने, जलापूर्ति की

audit और loss के मूल्यांकन के लिए आईटी उपकरणों का आधुनिकीकरण आदि अनेक प्रस्ताव सामने आए।

15. आउटकम आधारित बजटिंग से सरकार के कार्यक्रमों/परियोजनाओं की मॉनिटरिंग अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। सभी विभाग, कार्यक्रमों/परियोजनाओं के मॉनिटरिंग और विश्लेषण की महत्वता को समझ रहे हैं व मॉनिटरिंग की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को हल कर रहे हैं। नियमित डाटा संग्रह और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया जा रहा है, जहां आवश्यक है इसे मजबूत किया जा रहा है। मुझे इस बात का दृढ़ता से विश्वास है कि आउटकम बजट का प्रयोग समय के साथ और बेहतर होगा और जवाबदेही और शासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

XVIII. Way Forward

16. अध्यक्ष जी, मेरे प्रस्तुतिकरण से यही निष्कर्ष निकलता है कि आउटकम बजट हमारी सरकार का एक बड़ा बजट सुधार रहा है। मैं इस कवायद को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए योजना विभाग को बधाई देता हूँ। और अन्य सभी विभागों के अधिकारी, जिन्होंने इस प्रक्रिया में रचनात्मक योगदान दिया है, वे भी बधाई के पात्र हैं। परंतु यह केवल एक शुरुआत मात्र है और आउटकम बजट के सही लाभ हमें तभी मिलेंगे, जब हम सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में इस उपाय को संस्थागत रूप दे सकेंगे। आगामी वर्ष में यह सुनिश्चित करने के लिए हमने दो उपाय किए हैं। पहला यह है कि योजना विभाग एक आईटी अप्लीकेशन विकसित कर रहा है, जो बड़ी मात्रा में सृजित होने वाले आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण की समूची प्रक्रिया को सुचारु बनाएगा और इससे विभिन्न

योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की लगभग वास्तविक निगरानी संभव हो सकेगी। दूसरा यह है कि हमने योजना विभाग में एक **dedicated monitoring and evaluation unit** स्थापित करने और उसे मजबूत बनाने का निर्णय पहले ही कर लिया है। इससे दिल्ली सरकार की कार्य प्रणाली में आउटकम बजट प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा और उसे स्वतंत्र सर्वेक्षण और मूल्यांकन अध्ययन कराने में मदद मिलेगी।

17.अध्यक्ष जी, हमें पूरा यकीन है कि समूची सरकारी मशीनरी द्वारा परिणाम प्रदान किए जाने पर ध्यान केंद्रित करने की जो शुरुआत हमने दिल्ली में की है, उसका आने वाले वर्षों में समूचे देश में अनुकरण किया जाएगा।

18.योजना विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए आउटकम बजट भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी प्रति सभी माननीय सदस्यों को अप्रैल 2018 के अंत तक भेज दी जाएगी। 2018–19 के आउटकम बजट की एक प्रति योजना विभाग की वेबसाइट पर भी रहेगी, जिसमें वर्ष 2018–19 के लिए नियमित निगरानी के वास्ते विभिन्न **indicators** और **targets** के अलावा वर्ष 2017–18 की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाएगा।